बृहस्पतिवार
34 साल से देहरादून का विश्वास
05 नवम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 284
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94
email: doonvalley_news@yahoo.com
Website: dunvalleymail.com
डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

कार नदी में गिरी, 4 लोगों की मौत

◆एक गंभीर घायल, दो लापता



हमारे संवाददाता

उत्तरकाशी। सड़क हादसे में आज सुबह एक कार के खाई में गिर जाने से जहां चार लोगों की मौत हो गयी वहीं एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलने पर आपदा स्वंय सेवक व पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और मृतकों व घायल को अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी हालत चिंतांजनक बनी हुई है। वहीं हादसे में दो लोग लापता बताये जा रहे है जिनकी तलाश जारी है। कार सवार यात्री गुजरात के थे जिनकी चालक सहित संख्या 7 बतायी जा रही है।

मामला गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास का है। यहां आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गंगनानी से करीब 20 मीटर आगे डबरानी की ओर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद 4 लोगों के शव गाड़ी के किनारे पड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही आपदा स्वयं सेवक राजेश रावत एवं स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और नदी में गिरे घायल एवं शवों को बड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से सड़क तक लाया गया और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पहुंची और शवों की शिनाख्त का प्रयास किये। जिनकी पहचान श्रीमती पटेल अशोकबेन(49 वर्ष) निवासी 2दक फ्लोर शिवालिंग रेजीडेन्सी, ललिता चौकडी, कटारगम, सूरत सिटी गुजरात, सुश्री रुतिका अशोकभाई पटेल(19 वर्ष) निवासी 2 फ्लोर शिवालिक रेजीडेन्सी, ललिता चौकडी, कटारग, सूरत सिटी, गुजरात, घनश्याम भाई सरवालिया(32 वर्ष) निवासी गुजरात व सुरेन्द्र सिंह निवासी हरिद्वार(चालक)के रूप में की गयी है। वहीं घायल हुए युवक का नाम पटेल वेदान्त अशोकभाई(17 वर्ष), निवासी शिवालिंग रेजीडेन्सी, ललिता चौकडी, कटारगम, सूरत सिटी गुजरात बताया गया है। लापता लोगों के नाम श्रीमती पटेल सुधा बेन अशोकभाई(45 वर्ष), निवासी 2 फ्लोर शिवालिक रेजीडेन्सी, ललिता चौकडी, कटारगम, सूरत सिटी, गुजरात व श्रीमती पटेल किरनबेन विशालभाई(34 वर्ष), सरवालियाना चौरा पासे सायला, सुरेन्द्ररा नगर, गुजरात बताया गया है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई बसों को दिखाई हरी झंडी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीएस-06 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप इन नई बसों के परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार



एवं आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विशेष रूप से पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे गांवों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सड़क संपर्क के साथ ही सुदृढ़ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय निवासियों के साथ ही पर्यटकों को भी सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की इन 59 नई बसों का आवंटन प्रदेश के तीन मंडलों में किया गया है। इनमें नैनीताल मंडल को 19, टनकपुर मंडल को 20 तथा देहरादून मंडल को 20 बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों का संचालन आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा, जिससे आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बेड़े में कुल 1,276 बसें संचालित हैं, जिनमें निगम की अपनी 891 तथा 385 अनुबंधित बसें शामिल हैं। नई बसों के शामिल होने से निगम की सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। आधुनिक बीएस-06 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ये बसें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक योगदान देंगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को नई बस सेवाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड का प्रत्येक क्षेत्र बेहतर परिवहन सुविधाओं से जुड़े और विकास की यात्रा में कोई भी क्षेत्र पीछे न रहे।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, समाज कल्याण मंत्री खजान दास, विधायक भूपाल राम टम्टा, सचिव एवं परिवहन आयुक्त रविनाथ रामन सहित परिवहन विभाग एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दून वैली मेल

संपादकीय

अग्निपथ में बदलाव

किसी भी देश की सैन्य ताकत केवल आधुनिक हथियारों, तकनीक और सैन्य रणनीतियों से नहीं बनती, बल्कि उसकी असली ताकत उन जवानों के भरोसे में होती है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान और भविष्य दांव पर लगाते हैं। सैनिक के लिए वर्दी केवल नौकरी नहीं होती, यह सम्मान, पहचान, स्वाभिमान और जीवन का सपना होती है। इसलिए सेना में भर्ती की नीति बनाते समय केवल सैन्य जरूरतों और आर्थिक गणित को नहीं, बल्कि उन युवाओं के भविष्य को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जो देश की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बनाते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार का ताजा फैसला इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से पहले 25 प्रतिशत को योग्यता के आधार पर नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान था। शेष 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना था। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके बाद उनकी इच्छा और निर्धारित चयन मानकों के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा। अतिरिक्त सेवा अवधि में अधिक पारिश्रमिक, बेहतर सेवा निधि और वरिष्ठता संबंधी लाभ भी दिए जाएंगे। निस्संदेह, यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, जिनके सामने चार साल बाद सेना से बाहर होने का सवाल खड़ा था। सरकार ने कम से कम इतना स्वीकार तो किया है कि अग्निवीरों के प्रशिक्षण, अनुभव और सैन्य दक्षता का उपयोग चार साल बाद अचानक समाप्त कर देना व्यावहारिक नहीं है। चार साल में एक जवान को तैयार करने में सेना का समय, संसाधन और प्रशिक्षण खर्च होता है। ऐसे में प्रशिक्षित जवान को दो साल और सेवा का अवसर देना सैन्य संगठन की दृष्टि से भी तार्किक है। लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। क्या दो साल का विस्तार अग्निपथ योजना की मूल खामियों का समाधान है? क्या इससे युवाओं के मन में स्थायी रोजगार को लेकर पैदा हुई असुरक्षा समाप्त हो जाएगी? और क्या अब यह मान लिया जाए कि अग्निपथ योजना अपनी तमाम आलोचनाओं से मुक्त हो गई है? दरअसल, अग्निपथ योजना जब 2022 में लागू हुई थी, तब इसका सबसे बड़ा आधार सेना को युवा, ऊर्जावान और तकनीक के लिहाज से सक्षम बनाना बताया गया था। सरकार ने इसे सैन्य सुधार की दिशा में बड़ा कदम कहा। लेकिन इस योजना के साथ ही युवाओं के बीच भविष्य की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। चार साल की सेवा के बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा का अवसर मिलने की व्यवस्था ने उन युवाओं की चिंता बढ़ाई, जिनका सपना सेना में जाकर लंबे समय तक देश की सेवा करना था। यहां समझने की जरूरत है कि सेना की नौकरी और सामान्य सरकारी नौकरी में बुनियादी अंतर है। सेना में भर्ती होने वाला युवा केवल वेतन के लिए नहीं आता। वह अपने जीवन को अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा के साथ जोड़ता है। ऐसे में चार साल बाद सेवा समाप्त होने की आशंका उसके मन में स्वाभाविक रूप से असुरक्षा पैदा करती है। दो साल का विस्तार इस असुरक्षा को कुछ समय के लिए कम कर सकता है, लेकिन स्थायी भविष्य का सवाल तभी हल होगा, जब चयन प्रक्रिया और नियमित सेवा में समायोजन की व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट और भरोसेमंद होगी। सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। यदि अग्निवीरों को दो साल बाद नियमित सेवा में शामिल करने का रास्ता खोला जा रहा है, तो चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अग्निवीरों की इच्छा, योग्यता और निर्धारित मानकों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। किसी जवान को केवल इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि नीति के बदलाव और चयन की अस्पष्टता के बीच उसका भविष्य अधर में लटक गया। इस फैसले को अग्निपथ योजना की सफलता का प्रमाण बताना भी जल्दबाजी होगी। इसे योजना की समीक्षा के बाद सामने आया एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाना चाहिए। सरकार ने सेना से मिले सकारात्मक फीडबैक को आधार बनाया है, लेकिन सकारात्मक प्रदर्शन का अर्थ यह भी है कि इन जवानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए। यदि प्रशिक्षित और अनुभवी जवान सेना के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, तो उनके अनुभव को बनाए रखने की नीति को और मजबूत किया जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि सेना में भर्ती केवल संख्याओं का खेल नहीं हो सकती। जवानों की औसत आयु कम रखना, सैन्य खर्च का संतुलन बनाना और आधुनिक तकनीक के अनुरूप सेना को तैयार करना जरूरी है, लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया में युवाओं के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रसेवा का सपना दिखाकर युवाओं को भविष्य की अनिश्चितता के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। दो साल का सेवा विस्तार निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। इससे हजारों अग्निवीरों को राहत मिलेगी और सेना को प्रशिक्षित मानव संसाधन का लाभ भी मिलेगा। लेकिन सरकार को यह भी समझना होगा कि युवाओं को केवल समय का विस्तार नहीं, भविष्य का भरोसा चाहिए। वर्दी पहनने वाले नौजवान को यह भरोसा होना चाहिए कि उसके समर्पण, परिश्रम और सेवा का सम्मान होगा। अग्निपथ में दो साल का विस्तार एक सुधार है, समाधान नहीं। असली परीक्षा यह होगी कि सरकार अग्निवीरों के हाथ में केवल दो साल की अतिरिक्त सेवा नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी दे पाती है या नहीं।

धामी राज में सवाल पूछना है 'गुनाह'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। सत्ता को आईना दिखाना क्या अब उत्तराखंड में अपराध हो गया है? सरकार से सवाल पूछना क्या पुलिसिया कार्रवाई को न्योता देना है? और क्या लोकतंत्र में पत्रकार की कलम तभी तक आजाद है, जब तक वह सत्ता की मर्जी के मुताबिक लिखती रहे? रुद्रपुर के वरिष्ठ पत्रकार रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और अदालत से रिहाई के बाद ये सवाल प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। धामी सरकार के सामने अब सिर्फ एक पत्रकार की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस की जवाबदेही का बड़ा सवाल खड़ा है।

रूपेश सिंह की गिरफ्तारी ने जिस तरह प्रदेशभर के पत्रकारों और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा की, उसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन नवंबर की रात रुद्रपुर-काशीपुर हाईवे पर दानपुर के पास उनकी कार और एक बोलेरो के बीच टक्कर के बाद विवाद हुआ। बोलेरो सवार लोगों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया और चार नवंबर की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहां सवाल घटना से इनकार करने का नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई के तरीके का है। एक सड़क विवाद में हत्या के प्रयास जैसी संगीन धारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस ने दूसरे पक्ष की बात सुनी? क्या निष्पक्ष जांच के सभी जरूरी पहलुओं को परखा गया? या फिर गिरफ्तारी पहले और जांच बाद में करने का रास्ता चुना गया?

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अदालत से सामने आया। रूपेश सिंह को अदालत से राहत मिली और हत्या के प्रयास की धारा हटाई गई। जिस गंभीर आरोप के आधार पर पुलिस ने पत्रकार को गिरफ्तार किया था, उस पर न्यायिक स्तर पर सवाल खड़े होना पुलिस की शुरुआती कार्रवाई की समीक्षा की जरूरत को और बढ़ाता है। यह घटनाक्रम पुलिस के लिए भी असहज करने वाला है। आखिर इतनी संगीन धारा लगाने का आधार क्या था? क्या विवेचना में जल्दबाजी हुई? यदि आरोपों का आधार इतना मजबूत था तो अदालत में उसकी स्थिति क्या रही? इन सवालों का जवाब पुलिस को देना चाहिए।

◆रूपेश सिंह की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत, हत्या के प्रयास की संगीन धारा अदालत में नहीं टिकी
◆रिहाई के बाद पुलिस और सरकार पर बरसे पत्रकार, सत्ता के संरक्षण में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल
◆खाली कुर्सियों की खबर से सत्ता की त्यौरियां चढ़ीं? पत्रकार रूपेश सिंह की गिरफ्तारी पर मचा बवाल

रूपेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद रुद्रपुर कोतवाली विरोध का केंद्र बन गई। पत्रकारों, कांग्रेस नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित कई लोग विरोध में पहुंचे। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के विरोध के बीच पत्रकार को अदालत ले जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। यह विरोध सिर्फ रूपेश सिंह की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं था। इसके पीछे पत्रकारों में पनपता वह डर और आक्रोश भी दिखाई दिया, जो पुलिस की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। जब पत्रकारों को ही अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो सरकार के सुशासन के दावों की समीक्षा जरूरी हो जाती है।

अदालत से रिहा होने के बाद रूपेश सिंह ने मीडिया के सामने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी गतिविधियों पर नजर रखे जाने, उनके चौनल को बंद कराने के प्रयासों और राजनीतिक दबाव की आशंका भी जताई। हिरासत के दौरान मुलाकातों और मेडिकल परीक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनके आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यदि एक पत्रकार के यह आरोप सही हैं तो यह केवल पुलिस की कार्यशैली का मामला नहीं, बल्कि सत्ता और पुलिस के संबंधों की निष्पक्ष जांच का विषय है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

सत्ता अंकिता की मां की चीखों से 'बेपरवाह'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। एक मां की आंखों में आंसू हैं, आवाज में बेबसी है और दिल में अपनी बेटी को न्याय दिलाने की आखिरी उम्मीद। यह सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से सवाल है, जो न्याय का भरोसा तो देती है, लेकिन पीड़ित परिवार के सवालों का जवाब देने में अब भी असहज नजर आती है। अंकिता भंडारी की मां की भावुक पुकार एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर सामने आई उनकी पीड़ा भरी अपील ने भाजपा सरकार और संगठन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस भावुक अपील के साथ राजनीतिक संदेश भी बेहद तीखा है बेशर्म भाजपाइयों! अंकिता की मां की यह चीख-पुकार तुम्हारे अहंकार के अंत की आवाज बनेगी। यह केवल विपक्षी आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उस जनभावना का संकेत है, जो अंकिता प्रकरण में अब तक अनुत्तरित सवालों को लेकर लगातार मुखर होती रही है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। मामले में तीन आरोपियों को अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। एसआईटी जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी अंकिता के परिवार और आंदोलन से जुड़े लोगों के कुछ सवाल लगातार उठते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कथित वीआईपी की पहचान और उसकी भूमिका को लेकर है। अंकिता के माता-पिता की मांग रही है कि इस पहलू की निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो। परिवार की पीड़ा यह है कि बेटी को खोने के बाद भी उन्हें उन तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले, जिनके लिए वह लगातार आवाज उठा रहे हैं।

अंकिता प्रकरण अब केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तराखंड की राजनीति में संवेदनशीलता, जवाबदेही और सत्ता के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार भाजपा सरकार से वीआईपी प्रकरण पर जवाब मांग रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार अपनी ओर से हुई जांच और कानूनी कार्रवाई का हवाला देती रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है। क्या पीड़ित परिवार की हर आशंका का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या किसी मामले में अदालत से सजा हो जाने के बाद उससे जुड़े शेष सवालों पर संवाद की जरूरत समाप्त हो जाती है?

◆भाजपा के अहंकार पर भारी पड़ रहा है अब न्याय का सवाल
◆अंकिता की मां का दर्द बना उत्तराखंड की सियासत का केंद्र
◆सोशल मीडिया पर वायरल भावुक अपील ने भाजपा को घेरा
◆वीआईपी की पहचान के सवालों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें

इसी बीच उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण की वापसी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक ने पुराने मामले का उल्लेख कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। जवाब में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी भाजपा नेतृत्व पर पलटवार किया। इस राजनीतिक टकराव के बीच अंकिता की मां की पीड़ा फिर चर्चा में आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अंकिता प्रकरण के सवालों का जवाब देने के बजाय पुराने मामलों को उछालकर मूल मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है। हालांकि भाजपा का पक्ष है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के मामलों पर भी जवाब देना चाहिए।

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। भाजपा जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अंकिता प्रकरण को प्रमुख मुद्दा बना रही है। ऐसे में अंकिता की मां की भावुक अपील भाजपा के लिए राजनीतिक असहजता बढ़ाने वाली है। सत्ता के लिए चुनावी गणित महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कुछ सवाल राजनीति से कहीं बड़े होते हैं। अंकिता का मामला भी ऐसा ही है। पहाड़ की बेटी की हत्या और उसके बाद न्याय की मांग ने प्रदेश की सामूहिक चेतना को प्रभावित किया है। सरकार के सामने चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के भरोसे को मजबूत करने की भी है। लोकतंत्र में बहुमत सत्ता चलाने का अधिकार देता है, लेकिन सवालों से

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

कुंभ से पहले बहादराबाद और ज्वालापुर में बनेंगे 530 मीटर लंबे घाट

हरिद्वार(आरएनएस)। कुंभ-2027 की तैयारियों के तहत गंगा घाटों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बहादराबाद और ज्वालापुर में निर्माणाधीन तीन घाटों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति जांची। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। बहादराबाद में बैरियर संख्या छह के पास करीब 200 मीटर लंबे छठ पूजा घाट का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं, ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल के अपस्ट्रीम क्षेत्र में लगभग 300 मीटर और दुर्गा मंदिर के पास करीब 30 मीटर लंबे घाट का निर्माण कार्य चल रहा है। तीनों घाटों की कुल लंबाई करीब 530 मीटर होगी। इनके तैयार होने से स्थानीय लोगों के साथ ही धार्मिक आयोजनों में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। निरीक्षण के दौरान अपर मेलाधिकारी ने विशेष रूप से गंगनहर बंदी की अवधि का सदुपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों के जलमग्न रहने वाले हिस्सों का निर्माण प्राथमिकता से पूरा किया जाए।निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के साथ गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण भी कराया जाए। घाटों का निर्माण इस तरह किया जाए कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक स्नान की व्यवस्था मिल सके। ज्वालापुर के स्थानीय निवासियों और मंदिर समिति के सदस्यों ने घाट निर्माण के लिए सरकार और मेला प्रशासन का आभार जताया।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मांगा 4200 ग्रेड पे, आंदोलन की चेतावनी

हरिद्वार(आरएनएस)। पदोन्नति और ग्रेड पे समेत विभिन्न मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा ने महानिदेशालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने वार्ड बॉय, वार्ड आया, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और अनुसेवक के पदनाम बदलकर तकनीकी संवर्ग घोषित करने के साथ 4200 ग्रेड पे देने की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और असहयोग शुरू किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा और महामंत्री सुनील अधिकारी ने कहा कि मांगों को लेकर शासन और विभागीय स्तर पर चार बार समझौता हो चुका है, लेकिन अब तक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। उन्होंने लेब सहायक, डार्क रूम सहायक और ओटी सहायक के पदों पर पदोन्नति देने की मांग की। कहा कि पशुपालन और उद्यान विभाग की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए।प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत, उपाध्यक्ष नेल्सन अरोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र तेश्वर, जिला मंत्री राकेश भंवर, उपाध्यक्ष मूलचंद चौधरी, प्रदेश संगठन सचिव दिनेश गुसाईं और सुरेंद्र कश्यप ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और असहयोग के साथ उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।

पौंटी पुल पर वन विभाग ने बनाया नया चेकपोस्ट

उत्तरकाशी(आरएनएस)। बनाल और ठकराल क्षेत्र के देवदार के घने जंगलों से लकड़ी की अवैध तस्करी रोकने के लिए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। नौगांव-राजगढ़ी मोटर मार्ग पर पौंटी पुल के पास नया बैरियर चेकपोस्ट स्थापित किया गया है। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखने और अवैध रूप से लकड़ी ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। अपर यमुना वन प्रभाग के अंतर्गत बनाल और ठकराल क्षेत्र देवदार के घने जंगलों के लिए जाने जाते हैं। इन जंगलों से लकड़ी की अवैध निकासी की आशंका लंबे समय से बनी हुई है। नौगांव-राजगढ़ी मोटर मार्ग पर पहले वन विभाग का कोई बैरियर नहीं होने से इस रास्ते से लकड़ी की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पा रही थी। विभाग पूर्व में भी इस मार्ग पर अवैध रूप से लकड़ी ले जाते हुए तस्करों को पकड़ चुका है। बड़कोट क्षेत्र में अब तक वन विभाग का मुख्य बैरियर नगर पालिका क्षेत्र के बीच स्थित था। बनाल और ठकराल क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था नहीं होने के कारण खासकर रात के समय लकड़ी की अवैध ढुलाई की आशंका बनी रहती थी। अब पौंटी पुल पर नया चेकपोस्ट बनने से इस मार्ग पर वन विभाग की निगरानी बढ़ेगी। वन क्षेत्राधिकारी आशीष नौटियाल ने बताया कि चेकपोस्ट स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जंगलों से लकड़ी की अवैध तस्करी पर रोक लगाना है। इससे वाहनों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल तस्करी रोकना ही नहीं, बल्कि पेड़ों के अवैध कटान को रोकने के लिए भी सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

सियासत में लौटते चेहरों की भीड़

◆उत्तराखंड में 2027 की चुनावी आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट अभी पूरी तरह चुनावी बिगुल में नहीं बदली है, लेकिन सियासी मैदान में हलचल ऐसी है जैसे चुनाव कल ही होने वाले हों। राजनीतिक दलों के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के दौरे बढ़ने लगे हैं। कहीं पदयात्राएं निकल रही हैं, कहीं संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं तो कहीं कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस राजनीतिक सक्रियता के बीच सबसे दिलचस्प दृश्य उन दलों और नेताओं का है, जो पिछले पांच वर्षों तक लगभग राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहे। अब चुनाव नजदीक आते ही वे भी अपने-अपने राजनीतिक बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। किसी को जनता की याद सताने लगी है तो किसी को अचानक प्रदेश के विकास, बेरोजगारी, पलायन और क्षेत्रीय अस्मिता की चिंता होने लगी है।

उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी सक्रियता का यह दौर कई मायनों में दिलचस्प है। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए जमीन तैयार कर रही है। दोनों प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा संगठन की मजबूती, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा और भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हैं।

कांग्रेस ने जहां प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर रही है। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी ने चुनावी तैयारियों को और तेज करने के संकेत दिए हैं। वहीं भाजपा भी अपने राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के जरिए प्रदेश संगठन की चुनावी तैयारियों को धार दे रही है। साफ है कि अब उत्तराखंड की राजनीति केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में पहाड़ से मैदान तक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला और तेज होगा।

◆भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई दौड़भाग, हाशिये पर चले गए नेता हो गए सक्रिय
◆प्रदेश में पांच साल की खामोशी के बाद अचानक बढ़ गया है जनसंपर्क

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोचक पहलू उन नेताओं का है, जिन्हें पिछले पांच साल तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय देखना मुश्किल था। चुनाव के बाद कुछ नेता ऐसे गायब हुए कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी तक चर्चा का विषय नहीं रही। न जनता के बीच नियमित संवाद, न स्थानीय समस्याओं पर कोई प्रभावी आवाज और न ही संगठनात्मक गतिविधियों में उल्लेखनीय भागीदारी। लेकिन अब चुनाव का समय करीब आते ही इन नेताओं की राजनीतिक सक्रियता अचानक बढ़ गई है। कोई गांवों का दौरा कर रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगा है तो कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है।

इन नेताओं की सक्रियता का अपना राजनीतिक गणित है। पांच साल तक राजनीतिक जमीन से दूर रहने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया है कि यदि इस बार चुनावी दौड़ में शामिल नहीं हुए तो अगली पांच साल की राजनीतिक पारी हाथ से निकल सकती है। टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिन चेहरों को संगठन ने लंबे समय तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, वह भी अब अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन में जुटने लगे हैं। कुछ नेताओं को पार्टी से टिकट की उम्मीद है तो कुछ निर्दलीय अथवा नए राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं।

इस बार का चुनाव उन नेताओं के लिए भी आसान नहीं होगा, जो केवल चुनावी मौसम में जनता के बीच पहुंचने की परंपरा को राजनीति मान बैठे हैं। उत्तराखंड का मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक सवाल पूछ रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गांव-गांव में चर्चा का विषय हैं। पहाड़ के कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवाओं के सामने रोजगार का संकट आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में केवल बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करने या कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने से राजनीतिक स्वीकार्यता हासिल करना आसान नहीं होगा।

आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे। दल बदल की संभावनाएं, टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या, पुराने नेताओं की घर वापसी, नए चेहरों की दस्तक और बागियों की सक्रियता चुनावी परिदृश्य को और दिलचस्प बनाएगी। जिन नेताओं को अब तक राजनीतिक हाशिये पर रखा गया था, वह भी अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए जोर लगाएंगे। कुछ दल गठबंधन की संभावनाएं तलाशेंगे तो कुछ अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत आजमाने की तैयारी करेंगे।

उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही सियासी चेहरों का बाहर निकलना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार मतदाता के सामने भी फैसला करने का अवसर है। उसे यह तय करना है कि कौन नेता वास्तव में उसके बीच रहा और कौन केवल चुनावी मौसम का मेहमान है। क्योंकि इस बार मुकाबला केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि पांच साल के कामकाज और चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई सक्रियता के बीच भी होगा। सियासत में लौटते चेहरों की भीड़ भले ही बढ़ रही हो, लेकिन असली परीक्षा चुनावी मंच पर नहीं, जनता की अदालत में होगी। पांच साल तक जनता से दूरी बनाने वाले नेताओं को इस बार केवल अपना चेहरा नहीं, अपना हिसाब भी लेकर जाना पड़ेगा।

विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों में जुटा प्रशासन, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश

अल्मोड़ा(आरएनएस)। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह ने विकास भवन सभागार में निर्वाचन कार्यों के लिए नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने और आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने दायित्वों के अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें और उसके अनुसार तैयारियां पूरी करें। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों का समय रहते भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, प्रकाश व्यवस्था और पहुंच मार्ग सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहां कमियां पाई जाएं, वहां संबंधित विभागों से समन्वय कर समय रहते उन्हें दूर किया जाए, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं और निर्वाचन कार्मिकों को परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, मतदान सामग्री, परिवहन, संचार और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों का पूर्व आकलन कर व्यवस्थाओं की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी तैयारियां पूरी करें। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा सहित निर्वाचन कार्यों के लिए नामित सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।



'मातृशक्ति सम्मान समारोह' में महिलाओं को किया सम्मानित

हमारे संवाददाता

देहरादून। कैंट विधानसभा के इंदिरा नगर क्षेत्र स्थित रॉयल इन पैलेस वेडिंग पॉइंट में भव्य 'मातृशक्ति सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, भोजन माताओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम संयोजक एवं उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उन महिलाओं में बसती है, जो बिना किसी बड़े पद या पहचान की अपेक्षा के दिन-रात समाज की सेवा में जुटी रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और मातृ-शिशु स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाती हैं, आशा वर्कर्स स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाकर माताओं और बच्चों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहीं भोजन माताएं विद्यालयों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ उनके स्वास्थ्य और भविष्य को संवारने में योगदान देती हैं। ये महिलाएं समाज के हर वर्ग और हर परिवार तक पहुंचती हैं। इनके योगदान के बिना एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त समाज की कल्पना अधूरी है। कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उन लोगों को सम्मान देने की रही है, जिनका योगदान अक्सर मंचों और चर्चाओं से दूर रह जाता है। आज कांग्रेस ने समाज की इन वास्तविक नायिकाओं तक पहुंचकर उनका सम्मान करने का प्रयास किया है।

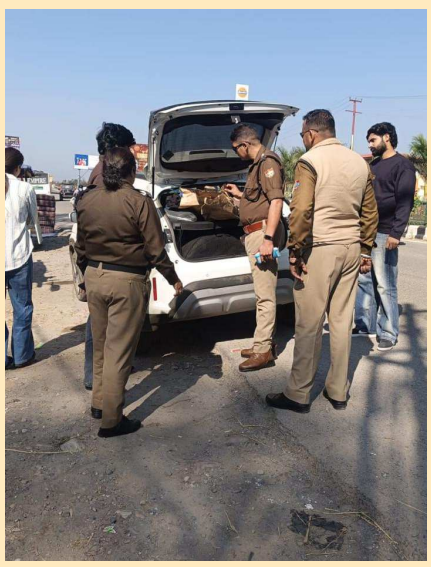
समारोह में आशाओं की प्रदेश अध्यक्ष शिवा दुबे, अनीता दास, विमलेश वर्मा, कामिनी कश्यप, राखी गुप्ता, उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला संयोजिका मधु पुंडीर, जिला अध्यक्ष तन्नू बम्बा, मीडिया प्रभारी गीता चौहान, सविता पुंडीर, संगीता भट्ट, सुनीता, निर्मला शर्मा एवं रीटा अग्रवाल सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, भोजन माताओं एवं विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ओबीसी विभाग की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, पिया थापा, पार्षद संगीता गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, सोशल मीडिया विभाग के महानगर अध्यक्ष गुरचरण कौशल, मधुसूदन सुंदरियाल, स्वाती नेगी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन भारती जोशी जी ने किया। अंत में अभिनव थापर ने सभी अतिथियों, सम्मानित महिलाओं एवं उपस्थित माताओं-बहनों का आभार व्यक्त किया।

वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए चलाया चैकिंग अभियान

हमारे संवाददाता

देहरादून। आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियो को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश हेतु सघन चैंकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों/सीमावर्ती चैक पोस्टों के साथ-साथ आन्तरिक मार्गों पर पुलिस द्वारा सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए बाहरी व्यक्तियों/वाहनों की सघन चैकिंग सुनिश्चित की जा रही है। चैकिंग के दौरान पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य बाजारों, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों आदी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए प्रभावी गश्त की जा रही है। साथ ही उक्त स्थानों पर लगातार सघन चैकिंग करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा होटल/धर्मशालाओं/गेस्ट हाउस आदी की सघन चैकिंग कर वहां रूके व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।



जनसभा व धनतेरस के दृष्टिगत परेड ग्राउंड के चारों तरफ रहेगा जीरो जान

संवाददाता

देहरादून। जनसभा के दृष्टिगत परेड ग्राउण्ड के चारों ओर यातायात को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु रोजगार तिराहे से सीजेएम तिराहा से लेंसडाऊन चौक तक सम्पूर्ण प्रकार के वाहनों के लिए जनसभा के दौरान जीरो जोन रहेगा।

आज यहां 6 नवंबर परेड ग्राउंड में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जनसभा, पुलिस लाइन देहरादून में अलंकरण परेड में अति विशिष्ट महानुभावो के सम्मिलित होने एवं धनतेरस पर्व के दृष्टिगत देहरादून शहर क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु निम्नलिखित डायवर्जन/ पार्किंग व्यवस्था। जनसभा के दृष्टिगत परेड ग्राउण्ड के चारों ओर यातायात को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु रोजगार तिराहे से सीजेएम तिराहा से लेंसडाऊन चौक तक सम्पूर्ण प्रकार के वाहनों के लिए जनसभा के दौरान जीरो जोन रहेगा। जनसभा के दृष्टिगत जीरो जोन के समय सर्वे चौक से ओरियण्ट चौक/लेंसडाऊन चौक की ओर जाने वाले वाहनों को रोजगार तिराहा से कनक चौक की ओर डायवर्ट करते हुए लैसडाउन चौक / ओरियण्ट चौक की ओर भेजा जायेगा। बुद्धा चौक से क्रॉस रोड की ओर जाने वाले वाहनों को एम.के.पी. के होते हुए भेजा जाएगा।

आराघर चौक से ईसी रोड की ओर जाने वाले वाहनों को सीएमआई चौक, एम.के.पी. चौक एवं बुद्धा चौक होते हुए सुभाष रोड होते हुए भेजा जाएगा। हरिद्वार/ऋषिकेश से आने वाली बसों के लिए रूट ख्ररिस्पना पुल- धर्मपुर चौक- आराघर, द्वारका स्टोर- सर्वे चौक- रोजगार तिराहा- पानी की टंकी के पास ड्रॉप, ब्श्रड तिराहा- एम.के.पी. रेस कोर्स- बन्नू स्कूल में पार्किंग। रुड़की/भगवानपुर/आई.एस.बी.टी से आने वाली बसों के लिए रूट ख्रपटेलनगर मंडी- सहारनपुर चौक- प्रिंस चौक- दर्शनलाल चौक- लैंसडाउन चौक- कनक चौक- दून क्लब के सामने ड्रॉप, ब्श्रड तिराहा- एम.के.पी.- रेस कोर्स- बन्नू स्कूल में पार्किंग। सहस्रधारा/रायपुर से आने वाली बसों के लिए रूट सहसधारा रोड- सहस्रधारा क्रॉसिंग- सर्वे चौक- सर्वे ऑफ इंडिया गेट के सामने ड्रॉप, द्वारका स्टोर-आराघर टी-जंक्शन से गुरुद्वारा ग्राउंड में पार्किंग। विकासनगर/ चकराता/ सहसपुर से आने वाली बसों के लिए रूट ख्र किशननगर चौक- बिन्दाल - घंटाघर-ओरियंट चौक- कनक चौक- दून क्लब के सामने ड्रॉप- ब्श्रड तिराहा- एम.के.पी. रेस कोर्स - गुरुद्वारा ग्राउंड में पार्किंग होगी।

पुलिस लाईन देहरादून में अलंकरण परेड के दौरान नेगी तिराहा से पुलिस लाईन पेट्रोल पम्प होते हुए बन्नू स्कूल चौक तक सम्पूर्ण प्रकार के वाहनों के लिए जीरो जोन रहेगा। पुलिस लाईन देहरादून में अलंकरण परेड में कार्यक्रम के दौरान नेगी तिराहा से बन्नू स्कूल की ओर जाने वाले वाहनों को नेगी तिराहा से गुरूनानक चौक की ओर भेजा जायेगा बन्नु चौक से नेगी तिराहा की ओर जाने वाले वाहन गुरूनानक/सूरी चौक होते हुये भेजे जायेंगे। लोडिंग वाहनों हेतु दर्शनी गेट, तिलक रोड, भण्डारी चौक, अन्सारी मार्ग, तहसील चौक, डिसपेन्सरी रोड, से पलटन बाजार में प्रवेश पुर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी लोडिंग वाहन प्रात: 10 बजे से 9 बजे तक पलटन बाजार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। केवल पैदल यात्री ही प्रवेश कर सकेगें।

सर्वे चौक पर यातायात का दबाव अधिक होने पर रायपुर से आने वाले यातायात को कर्जन रोड तिराहा से म्यूनिसिपल रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा। घण्टाघर पर यातायात का दबाव अधिक होने की स्थिति मे राजपुर रोड़ की ओर से आने वाले यातायात को ओरिएन्ट चौक से कनक चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा एवं दर्शनलाल से घण्टाघर की ओर आने वाले यातायात को लैन्सडाउन चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा। धर्मपुर चौक पर यातायात के दबाव की स्थिति में माता मंदिर रोड से आने वाले यातायात को रेसकोर्स की ओर डायवर्ट किया जायेगा एवं नेहरु कॉलोनी तिराहा से धर्मपुर जाने वाले यातायात को फब्बारा चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा।

परेड ग्राउंड में जनसभा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए विक्रमों का भी डायवर्जन प्रभावी किया जायेगा। निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को पार्क कर असुविध ा से बचें तथा अपने लोकल बाजारों में ही खरीदारी करें, एवं दोपहिया वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। समस्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने परिसर की बेसमेंट पार्किंग को आमजन हेतु अवश्य खुला रखें। अन्यथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

परेड ग्राउंड में जनसभा एवं धनतेरस पर्व के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में यातायात का दबाव अधिक रहने की संभावना है। अत: यातायात पुलिस देहरादून आमजन से अपील करती है कि असुविधा से बचने हेतु यथासंभव दोपहिया वाहनों अथवा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यातायात पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी एवं डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें तथा यथासंभव स्थानीय बाजारों से खरीदारी करें। आमजन से अनुरोध है कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें ।

शब्द सामर्थ्य - 58

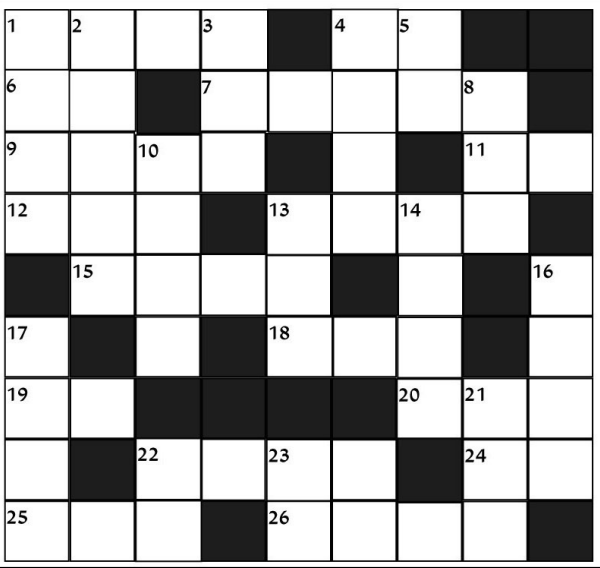
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जल छिड़कना, राजा के सिंहासन रोहन का अनुष्ठान 4. मवाद, पीब (अं) 6. जाति 7. हाथ से धीरे-धीरे ठोंकना, थपकना 9. कमल रोग से ग्रसित व्यक्ति (उ.) 11. किरण 12. छौंक, तड़का 13. दुखदायी, दर्दनाक 15. विवाद, कहासुनी, तकरार 18. समूह, दल, समुदाय 19. दण्ड 20. काजल 22. अनाथ, निराश्रित, यतीम 24. दुख, शोक 25. एक प्रसिद्ध सफेद पक्षी, वक 26. राज्य का विदेश में प्रतिनिधि।

ऊपर से नीचे

1. विचित्र, अद्भूत 2. अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना 3. वचन, वाणी 4. गुमराह, जो रास्ते से भटक गया हो 5. मुलायम सिंह की पार्टी का संक्षिप्त नाम 8. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध देवर्षि 10. कार्यावली, करस्तानी, प्रशंसनीय कार्य 13. दासी, नौकरानी, बांदी, गुलाम स्त्री 14. प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, आविष्कारक 16. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर 17. सामान (उ.) 21. संसार, दुनिया 22. समय, चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 23. पराजित, परास्त।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 57 का हल

दि	क्क	त	■	आ	सा	न	■	आ
ल	■	मी	■	खि	■	सी	ख	ना
■	म	ज	बू	र	■	ह	■	जा
स	र्द	■	■	का	■	त	रा	ना
र	■	■	■	र	वि	■	ह	■
प	ह	ना	ना	■	ना	रा	ज	■
ट	■	■	क	शि	श	■	नी	ला
■	र	■	■	का	■	रा	■	य
खा	ति	र	दा	री	■	त	क्ष	क

रवि तेजा और विवेक आत्रेय की नई फिल्म तुलाभारम' का आगाज!

दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित अभिनेता रवि तेजा और निर्देशक विवेक आत्रेय अपनी आगामी फिल्म तुलाभारम' के लिए पहली बार साथ आए हैं। फिल्म का शुभारंभ पारंपरिक पूजा समारोह के साथ किया गया। ब्रिज प्रोडक्शंस के बैनर तले लक्ष्मण और श्रीनी राव इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में रवि तेजा की दमदार अभिनय शैली के साथ विवेक आत्रेय की अलग तरह की कहानी कहने की कला देखने को मिलेगी। इसे अपराध पर आधारित नाटकीय फिल्म बताया जा रहा है।

फिल्म के निर्माताओं ने एक विशेष वीडियो के माध्यम से इसके शीर्षक की घोषणा की। द टाइटल डॉक्यूमेंट्री' नाम से तैयार इस वीडियो को माई होम राम' ने जारी किया। मनोरंजक और हास्यपूर्ण अंदाज में बनाए गए इस वीडियो में फिल्म के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनने के दौरान टीम के अनुभवों और दिलचस्प घटनाओं को दिखाया गया है। इस अनूठे प्रचार वीडियो ने फिल्म की कहानी और इसके पीछे काम कर रही रचनात्मक टीम को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म की विषयवस्तु और कलाकारों के संयोजन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। रवि तेजा को आमतौर पर उनकी दमदार पर्दे पर मौजूदगी और जोशीले किरदारों के लिए मास महाराजा' कहा जाता है। हालांकि, तुलाभारम' की घोषणा में उन्हें क्राइम महाराजा' के रूप में पेश किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि फिल्म में दर्शकों को उनके अभिनय का एक अलग अंदाज देखने को मिल सकता है।

फिल्म के शीर्षक संबंधी वीडियो में अन्य प्रमुख कलाकारों के किरदारों का भी परिचय दिया गया। तरुण भास्कर देवराज, प्रियंका मोहन कृष्णवेणी, अनस्वरा राजन साउंड, जेडी चक्रवर्ती शिवाजी राव, अनिल करेला जडेजा और रवि एंथनी रॉबिन की भूमिका निभाएंगे। फिल्म के शुभारंभ समारोह में दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं। निर्देशक वी.वी. विनायक ने फिल्म की पटकथा सौंपी, जबकि चंदू ने कैमरा चालू किया और अभिनेता श्री विष्णु ने क्लैपबोर्ड बजाकर फिल्म की शुरुआत का संकेत दिया। शिवा निर्वाण और बॉबी ने फिल्म का पहला दृश्य निर्देशित किया।

तुलाभारम' के संगीत की जिम्मेदारी विवेक सागर को सौंपी गई है। थेनी ईश्वर आईएससी फिल्म के छायांकन का काम संभालेंगे, जबकि रवितेजा गिरिजाला संपादन करेंगे। वहीं, जीएम शेखर फिल्म के कला निर्देशन और निर्माण संबंधी दृश्यात्मक तैयारियों की जिम्मेदारी निभाएंगे।

फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। रवि तेजा और विवेक आत्रेय की इस नई जोड़ी से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, फिल्म की कहानी, रिलीज की तारीख और अन्य विवरणों को लेकर निर्माताओं की ओर से आगे की घोषणाओं का इंतजार है।

20 दिसंबर को हो सकता है बिग बॉस 20' का महा-मुकाबला!

अभिनेता सलमान खान के लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 20' ने अपने सफर के डेढ़ महीने पूरे कर लिए हैं। आमतौर पर करीब तीन महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के मौजूदा सत्र के भी साल के अंत तक समाप्त होने की संभावना है। इस बीच शो के महा-मुकाबले यानी ग्रैंड फिनाले की तारीख को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, निर्माताओं ने 20 दिसंबर 2026 को फिनाले आयोजित करने की योजना बनाई है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फिनाले की संभावित तारीख को लेकर अटकलें हाल ही में प्रसारित वीकेंड का वार' कार्यक्रम के बाद शुरू हुईं। बताया जा रहा है कि इस कड़ी में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने प्रतियोगियों को संकेत दिया कि वे शो का आधा सफर पूरा कर चुके हैं और विजेता की घोषणा होने में अब केवल आठ सप्ताह शेष हैं। इसके बाद से ही दर्शकों के बीच फिनाले की तारीख को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

सोशल मीडिया पर भी शो के प्रशंसक अपने पसंदीदा प्रतियोगियों का समर्थन कर रहे हैं। दर्शक उन्हें विजेता बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले सप्ताह प्रतियोगियों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि हर मुकाबले के साथ विजेता की दौड़ और दिलचस्प होती जा रही है।

बिग बॉस 20' के प्रसारण की शुरुआत से अब तक रोहैद खान, रिति तिवारी, अमन गांधी, ईशा रिखी और मुक्केबाज मैरी कॉम समेत कई प्रतियोगी घर से बाहर हो चुके हैं। लगातार हो रहे निष्कासनों के बाद अब घर में केवल 12 प्रतियोगी बचे हैं, जो विजेता की ट्रॉफी हासिल करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

मौजूदा प्रतियोगियों में आम्रपाली दुबे, यंग डीएसए, स्काउट ओपी, आसिफ खान, लव गिल, अरिश्फा खान, उदिति सिंह, माही गिल, काजी तौकीर, गुल्लू, कनिका मान और मनीष गोयल शामिल हैं।

शो के अंतिम चरण की ओर बढ़ने के साथ प्रतियोगियों के बीच मुकाबला और कड़ा होने की उम्मीद है। दर्शकों की पसंद, प्रतियोगियों का प्रदर्शन और आने वाले सप्ताहों में होने वाले मुकाबले विजेता की दौड़ को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 20 दिसंबर को ही कार्यक्रम का समापन होगा या निर्माताओं की ओर से तारीख में कोई बदलाव किया जाएगा। अब सभी की निगाहें निर्माताओं की आधिकारिक घोषणा और उन 12 प्रतियोगियों पर टिकी हैं, जिनमें से किसी एक के हाथ आखिरकार बिग बॉस 20' की विजेता ट्रॉफी लगेगी।

बैचलर पार्टी डीयू में ज्योतिर्मयी निभाएंगी पॉली का किरदार!



मलयालम फिल्ममेकर अमल नीरद की अपकमिंग फिल्म बैचलर पार्टी डीयू को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। अब मेकर्स ने फिल्म में एक्ट्रेस ज्योतिर्मयी के किरदार का नाम भी सामने ला दिया है। वह फिल्म में पॉली के किरदार में नजर आएंगी। डायरेक्टर अमल नीरद ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए लिखा, ज्योतिर्मयी इज पॉली। यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई अमल नीरद की सफल फिल्म बैचलर पार्टी का सीक्वल है। यही वजह है कि फिल्म को लेकर फैंस के बीच खास दिलचस्पी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, नई फिल्म की कहानी पिछली फिल्म से जुड़ी होगी, लेकिन इसमें कई नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। बैचलर पार्टी डीयू में एक बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी। फिल्म में प्रेमलु से देशभर में पहचान बनाने वाले एक्टर नसलेन लीड रोल में हैं। उनके अलावा कुंचाको बोबन, टोविनो थॉमस, सौबिन शाहिर, श्रीनाथ भासी, शराफुद्दीन, शाइन टॉम चाको, चंदू सलीमकुमार, रजीशा विजयन, हंसिका कृष्णा और पेरिस लक्ष्मी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

मेकर्स इससे पहले फिल्म में नादिया मोइदू और रजीशा विजयन के किरदारों के नाम का भी खुलासा किया था। नादिया फिल्म में अन्ना मैथ्यूज का किरदार निभा रही हैं, जबकि रजीशा विजयन सिंपल के रोल में दिखाई देंगी।

फिल्म में शाइन टॉम चाको गुरु, चंदू सलीमकुमार मम्मू, श्रीनाथ भासी जावी और शराफुद्दीन पप्पन के किरदार में नजर आएंगे। वहीं, सौबिन शाहिर फिल्म में डैनी की भूमिका निभा रहे हैं।

हालांकि, टोविनो थॉमस के किरदार को लेकर मेकर्स ने अब तक सस्पेंस बनाए रखा है। फिल्म से उनका लुक सामने आ चुका है, लेकिन उनके किरदार का नाम नहीं बताया गया है। टोविनो के पोस्टर जारी करते हुए अमल नीरद ने मशहूर अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर की एक पंक्ति भी लिखी थी, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। इस पंक्ति का मतलब है कि नरक खाली है और सारे शैतान यहां मौजूद हैं। डायरेक्टर की इस पोस्ट ने फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। बैचलर पार्टी डीयू इसी साल 19 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कैदी बने अमित साध, बदल गई पूरी दुनिया!

मुंबई क्या होता है जब जिंदगी भर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला एक पुलिस अधिकारी खुद कानून के शिकंजे में फंस जाता है? अमित साध और ईशा देओल स्टारर आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म प्रताप' के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है।

ट्रेलर में एक जांबाज और सम्मानित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिंदगी में आए उस असाधारण मोड़ की झलक देखने को मिलती है, जो उसकी पूरी दुनिया बदलकर रख देता है। फिल्म में अमित साध प्रताप नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब वह खुद सलाखों के पीछे पहुंच जाता है।

ट्रेलर में उसके अतीत और वर्तमान के बीच की कहानी दिखाई गई है, जो कई सवाल खड़े करती है। आखिर किन परिस्थितियों में प्रताप को जेल जाना पड़ता है और अब उसके सामने कौन-सी चुनौतियां आती हैं? दमदार टकराव, एक्शन से भरपूर सीक्वेंस और अप्रत्याशित घटनाक्रम ट्रेलर को दिलचस्प बनाते हैं। कभी कानून की रक्षा करने वाला यह अधिकारी अब खुद अपनी लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है।

फिल्म में ईशा देओल और उनके साथ कई अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अमित साध कहते हैं, प्रताप कोई पारंपरिक पुलिसवाले की कहानी नहीं है। यही वजह है कि मुझे इस किरदार की यात्रा ने आकर्षित किया। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून लागू करने में बिताई, लेकिन एक दिन खुद कानून के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है।

इस किरदार के भीतर कई भावनाएं और विरोधाभास हैं, जिन्हें निभाना एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए दिलचस्प था। ट्रेलर आपको उसकी दुनिया की एक झलक देता है, लेकिन उसकी कहानी में अभी बहुत कुछ ऐसा है, जो पर्दे पर सामने आना बाकी है। वहीं, ईशा देओल कहती हैं, मुझे प्रताप' की कहानी की सबसे खास बात यह लगी कि यह ऊपर से जितनी सीधी-सादी दिखाई देती है, असल में उतनी है नहीं।

इसकी कहानी में कई परतें हैं और जैसे-जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, आप किरदारों और उनकी परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अमित और सचिन के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा। मैं चाहती हूं कि दर्शक फिल्म देखें और जानें कि इसमें उनके लिए क्या खास है। फिल्म के लेखक-निर्देशक सचिन सराफ कहते हैं, 'प्रताप' के जरिए मैं एक ऐसे इंसान की कहानी कहना चाहता था, जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब वह खुद को ऐसी परिस्थिति में पाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

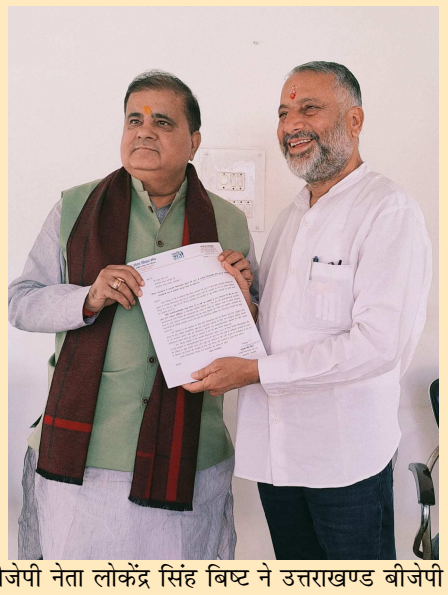
यह फिल्म फैसलों, उनके नतीजों और सही-गलत के बीच की बारीक रेखा की कहानी है। हमने एक्शन और भावनाओं को कहानी की जरूरत के मुताबिक रखते हुए इसे वास्तविकता के करीब दिखाने की कोशिश की है। ट्रेलर तो बस उस कहानी की शुरुआत है, जो फिल्म में आगे खुलकर सामने आएगी। निर्माता प्रदीप रंगवानी कहते हैं, 'प्रताप' ऐसी फिल्म है, जिसे बनाने में हमने बहुत मेहनत की है और जिस पर हमें पूरा विश्वास है।

शुरुआत से ही हमें सचिन के विजन और उनकी कहानी पर भरोसा था। अमित ने अपने किरदार में गहराई लाई है और फिल्म में अनुभवी कलाकारों की शानदार टीम भी है, जो इसकी कहानी को और मजबूत बनाती है। हमें खुशी है कि आखिरकार हम दर्शकों के साथ फिल्म का ट्रेलर साझा कर रहे हैं। अब हम 20 नवंबर को प्रताप' को सिनेमाघरों में लाने के लिए उत्साहित हैं। सचिन सराफ द्वारा लिखित और निर्देशित प्रताप' में अमित साध और ईशा देओल के अलावा सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया और मिलिंद गुणाजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्रदीप रंगवानी द्वारा निर्मित और यूवी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर गंगोत्री विधानसभा से अपनी दावेदारी विधिवत प्रस्तुत की

संवाददाता

देहरादून। गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी के संभावित प्रबल दावेदार लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने पिछले सप्ताह दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से लेकर राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी सहित तमाम नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के बाद आज देहरादून बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो राज्यसभा सांसद माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी से मुलाकात कर अपनी दावेदारी विधिवत प्रस्तुत की।



इससे पहले बीजेपी नेता ने उत्तराखण्ड के सबसे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र जैसे राज्य के राज्यपाल रहे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मिलकर आशीर्वाद लिया।। अपने सघन अभियान में जुट बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने उत्तराखण्ड बीजेपी के महामंत्री श्री कुंदन परिहार, महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज, उत्तरकाशी जिले प्रभारी श्री नवीन ठाकुर से मुलाकात कर विधिवत अपना आवेदन और जीवन वृत्त सौंपकर अपने द्वारा गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए सामाजिक कार्यों, विकास कार्यों की सूची सौंपकर आने वाले समय में गंगोत्री विधानसभा के विकास के लिए अपना रोड मैप प्रस्तुत किया।।

गौरतलब है कि वर्ष 2027 में फरवरी में उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव में गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी के प्रबल दावेदार बीजेपी के नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी के दावेदार पेशे से पत्रकार रहे हैं। 4 नवंबर को बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने उत्तराखण्ड के कद्दावर नेता श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मिलकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखण्ड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सकारात्मक चर्चा हुई है। खासकर गंगोत्री विधानसभा को लेकर बिष्ट ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा।

लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्होंने गंगोत्री विधानसभा का समुचित विकास के संकल्प को लेकर एक रोड मैप के साथ अपनी बात रखी और अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से अवगत कराया। इस मुलाकात के दौरान गंगोत्री विधानसभा के विकास और आगामी चुनाव को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

सू- दोकू क्र. 58

	2		6		8		3	
9		8		3		4		
							5	
5		2			7		6	
	8		4			1		3
				9				
8			9				1	
	5			1		6		2
		1	7				4	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 57 का हल

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5		6	2
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

महिलाओं और बालिकाओं को साइबर ठगी से बचाव के तरीके बताए, गौरा शक्ति ऐप की दी जानकारी

अल्मोड़ा(आरएनएस)। महिलाओं और बालिकाओं को साइबर अपराधों तथा उनकी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए अल्मोड़ा पुलिस का अभियान जारी है।

इसी क्रम में महिला कोतवाली पुलिस ने विशाल मेगा मार्ट और अल्मोड़ा बाजार में जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, घरेलू हिंसा और मानव तस्करी के प्रति जागरूक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर जिले में साइबर जागरूकता 2.० अभियान चलाया जा रहा है। महिला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जानकी भंडारी के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल रजनी जोशी और उषा ने बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचीं महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया। पुलिस टीम ने उन्हें साइबर ठगी के बढ़ते मामलों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी और बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध क्यूआर कोड स्कैन करने और अज्ञात व्यक्तियों के संदेशों पर भरोसा करने से बचें। पुलिस कर्मियों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी के बारे में भी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस, सीबीआई या कोई अन्य जांच एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। इसके अलावा इनाम, लॉटरी और अन्य आकर्षक प्रलोभन देकर पैसे मांगने वालों से सतर्क रहने की सलाह दी। अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को बच्चों से संबंधित अपराधों, घरेलू हिंसा अधिनियम और मानव तस्करी के बारे में भी जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप की उपयोगिता और सुविधाओं के बारे में बताते हुए पुलिस टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं के मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड कराया।

पुलिस ने आपातकालीन स्थिति में डायल 112 और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 193० पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी।

गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार पर उतरे प्राथमिक शिक्षक

उत्तरकाशी(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय समिति के आह्वान पर जिले के प्राथमिक शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष जयदेव सिंह राणा के नेतृत्व में शिक्षकों ने एक नवंबर से आंदोलन शुरू करते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से सौंपे जाने वाले कार्यों में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। संघ के जिलाध्यक्ष जयदेव सिंह राणा ने बताया कि शिक्षक अब केवल शिक्षण कार्य, छात्र उपस्थिति दर्ज करने और पीएम पोषण योजना से जुड़े दायित्वों का ही निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। शिक्षकों ने एक अक्तूबर 2००5 के बाद नियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग भी उठाई। कहा कि शिक्षण कार्य के अलावा विभिन्न ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कोर्स और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव बनाया जा रहा है। कोर्स पूरा नहीं करने पर वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की चेतावनी से शिक्षकों में नाराजगी है। अतिरिक्त कार्यों के कारण कक्षा शिक्षण और पाठ्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।

डॉ. गंगवार डीन टेक और डॉ. तिवारी बने निदेशक प्रसार शिक्षा

रुद्रपुर(आरएनएस)। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि कार्यहित एवं प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्राध्यापकों के प्रशासनिक दायित्वों में फेरबदल किया गया है। इसके तहत डॉ. राकेश पाल सिंह गंगवार को जहां अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बनाया गया। वहीं डॉ. चंद्रेश्वर तिवारी को निदेशक प्रसार शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है। विवि के कार्मिक प्रबंधन अनुभाग (ए) की ओर से जारी आदेश के तहत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. एसएस गुप्ता के सेवानिवृत्त होने पर कुलपति ने उन्हें 31 अक्तूबर को डीन टेक के कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। साथ ही उनके आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक डॉ. आरपीएस गंगवार को वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित डीन की नियुक्ति होने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, डीन टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।वहीं केवीके काशीपुर के प्रभारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र क्षात्रा के स्थान पर डॉ. चंदेश्वर तिवारी प्राध्यापक (कृषि विज्ञान) और प्रभारी अधिकारी केवीके अल्मोड़ा को उनके स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रसार शिक्षा निदेशक का कार्यभार अगले आदेश तक सौंपा गया है। डॉ. गंगवार और डॉ. तिवारी को प्रबंधन बोर्ड की ओर से अनुमन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए सभी लाभ प्राप्त होंगे। जबकि उनकी सेवा शर्तें और नियम अपरिवर्तित रहेंगे। जबकि उच्च न्यायालय के 25 मार्च 2०25 के आदेश के अनुपालन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक डॉ. लोकेश वार्ष्णेय स्नातकोत्तर अध्ययन (पीजीएस) के डीन के रूप में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने तीन-चार दिन पूर्व इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

डीडीहाट में बगैर फिटनेस-इंश्योरेंस के दौड़ रही बस सीज

पिथौरागढ़(आरएनएस)। डीडीहाट में परिवहन विभाग ने बगैर फिटनेस-इंश्योरेंस के दौड़ रही एक बस को सीज किया। एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल ने बताया कि क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को ले जा रही एक बस रोकी गई। जांच के दौरान वाहन का फिटनेस और इंश्योरेंस न मिलने पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए बस सीज की गई। एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि दिवाली पर्व के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने, यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि व वाहनों के अधिक संचालन को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों के आवश्यक अभिलेखों, फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस व वाहन की निर्धारित यात्री क्षमता की जांच की जा रही है। बताया कि बीते माह जनपद में 612 चालान और 14 वाहन सीज किए गए।

अशासकीय माध्यमिक शिक्षकों को तीन माह से नहीं मिला वेतन

नई टिहरी(आरएनएस)। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने दो माह से वेतन नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अशासकीय स्कूलों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया बना हुआ है। वेतन भुगतान शीघ्र नहीं किया जाता है, तो शिक्षकों को धनतेरस के दिन धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल नौटियाल की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई बैठक में संघ ने अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों का वेतन बजट अभी तक स्वीकृत नहीं करने पर नाराजगी जताई है। प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री महादेव मैठाणी ने कहा कि अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों को दो-तीन माह से वेतन नहीं मिल पाया है जबकि बजट की मांग एक माह पहले ही निदेशालय को भेज दी गई थी लेकिन शासन की लापरवाही के कारण वेतन बजट की पत्रावली शासन स्तर पर लंबित पड़ी हुई है।

संघ ने महानिदेशक शिक्षा को भी ज्ञापन देकर शीघ्र बजट जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पांच नवंबर तक वेतन बजट स्वीकृत नहीं मिलती है, तो छह नवंबर को धनतेरस के दिन निदेशालय में धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, तो उन्हें दीपावली का त्योहार मनाना मुश्किल हो जाएगा। ऑन लाइन बैठक में संघ के प्रांतीय संरक्षक संजय बिजल्वाण, मंडलीय अध्यक्ष शिव सिंह रावत, मनोज रावत, कुमांऊ मंडल अध्यक्ष विशन सिंह मेहता, मंडल मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह मेहरा, जिलाध्यक्ष देहरादून दिनेश डोबरियाल, जिला मंत्री महावीर सिंह मेहता, गिरीश सेमवाल, टिहरी जिलाध्यक्ष शिव सिंह रावत, जिलामंत्री नवीन बडोनी, जिलाध्यक्ष चमोली नरेंद्र सिंह रावत, जिलामंत्री दीपचंद्र सती, जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग बलवीर सिंह रौथाण, जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह बर्तवाल, जिलाध्यक्ष पौड़ी देवेंद्र सिंह, ज़िला मंत्री मनीष भूषण सारंग, जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा हीरा सिंह मेहरा ,प्रकाश खोलिया, अनिल भट्ट, हरिद्वार से दीपक मिश्रा शामिल हुए।



मुख्यमंत्री ने बृजमोहन सिंह रावत को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के बडे भाई स्वर्गीय बृजमोहन सिंह रावत के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी पहुंचकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई स्वर्गीय बृजमोहन सिंह रावत की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

सत्ता अंकिता की मां की चीखों से..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

बचने का लाइसेंस नहीं।

अंकिता की मां की आवाज को राजनीतिक शोर समझकर नजरअंदाज करना भाजपा के लिए बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि मां की आंखों के आंसू किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होते। वह न्याय की मांग करते हैं। और जब न्याय की यह पुकार सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर भी अनसुनी महसूस होने लगे, तब वह केवल एक परिवार का दर्द नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन जाती है।

धामी राज में सवाल पूछना है 'गुनाह'...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

इस प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक कार्यक्रम की कवरेज और वहां खाली कुर्सियों के वीडियो प्रसारित होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप है कि कार्यक्रम से जुड़ी कुछ सोशल मीडिया सामग्री हटाई गई। रूपेश सिंह की गिरफ्तारी और इस कवरेज के बीच सीधा संबंध अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन इन घटनाओं के एक साथ चर्चा में आने से राजनीतिक सवालों को हवा जरूर मिली है। आखिर सत्ता को आईना दिखाने वाली खबरों से इतनी परेशानी क्यों होनी चाहिए? यदि किसी पत्रकार की रिपोर्ट गलत है तो उसका जवाब तथ्य और कानून से दिया जाना चाहिए, न कि ऐसी कार्रवाई से जो पत्रकारिता जगत में भय का माहौल पैदा करे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर उत्तराखंड को विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सुशासन की असली पहचान केवल सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों और मंचों से किए जाने वाले दावों में नहीं होती। उसकी असली परीक्षा सत्ता की आलोचना सहने की क्षमता में होती है। रूपेश सिंह प्रकरण में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पत्रकार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा होगी? क्या संगीन धाराओं के इस्तेमाल की जवाबदेही तय होगी? और क्या प्रदेश में पत्रकारों को बिना किसी दबाव के सरकार से सवाल पूछने की गारंटी मिलेगी?

लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होतीं, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता लंबे समय तक याद रखी जाती है। पुलिस की वर्दी कानून की रक्षा के लिए है, सत्ता की असहजता दूर करने के लिए नहीं। पत्रकारिता का काम सरकार की प्रशंसा में कसीदे पढ़ना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को सत्ता तक पहुंचाना है। रूपेश सिंह की रिहाई के बाद अब सवाल सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में कलम को आजाद रहने दिया जाएगा या हर असहज सवाल के सामने पुलिस की ताकत खड़ी कर दी जाएगी?

चरस के साथ गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने चरस के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुर थाना पुलिस ने जोहडी गांव जाखन मजार के पास एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो 110 ग्राम चरस बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम अशद उर्फ सुभान खान पुत्र वकिल खान निवासी मोथरोवाला नौका विहार बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

'दिल की बात, अंकल धामी के साथ': मुख्यमंत्री ने 8 लाख स्कूली बच्चों को वर्चुअल किया संबोधित

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख स्कूली बच्चों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से 'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख स्कूली बच्चों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख स्कूली बच्चों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए त्योहारों के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, स्वच्छता, सुरक्षा, पढ़ाई तथा भविष्य के लक्ष्यों को लेकर प्रेरक संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के बच्चों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखना, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षा, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों में अध्ययनरत लाखों बच्चे



एक साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को आत्मीयता से संबोधित करते हुए उनके परिवार के सदस्यों का हालचाल पूछा और दीपावली की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं हैं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने तथा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम भी हैं। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे पर्व हमें आपसी प्रेम, सहयोग और पारिवारिक संबंधों के महत्व का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए बच्चों से पटाखों से दूर रहने तथा दीये एवं फुलझड़ियां जलाते समय बड़ों की देखरेख में रहने को कहा। उन्होंने कहा कि त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी है, जब हम स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की भी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और नई चीजें सीखने में भी रुचि लेनी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की भावना आवश्यक है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 'दिल की बात, अंकल धामी के साथ' कार्यक्रम को भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से और उपयोगी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी ढ़ाई लाख से अधिक विद्यार्थियों ने निबंध के माध्यम से आयोजित संवाद कार्यक्रम में उत्तराखण्ड के विकास को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के विचारों और सुझावों का विशेष महत्व है। उनसे प्राप्त उपयोगी सुझावों पर भविष्य की योजनाओं और नीतियों के निर्माण में भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे खूब पढ़ें, खूब खेलें, नई चीजें सीखें और अपनी प्रतिभा से माता-पिता, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मक सोच विकसित उत्तराखण्ड एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस अवसर पर सचिव शिक्षा सुश्री ज्योति यादव, महानिदेशक शिक्षा श्रीमती आकांक्षा कोंडे, सयुंक्त निदेशक गोविन्द राम जायसवाल मौजूद थे।

मोहब्बेवाला में हो रही दुर्घटनाओं के चलते एनएचएआई व पीडब्लूडी पर मुकदमा

संवाददाता

देहरादून। मोहब्बेवाला में आये दिन हो रहे दुर्घटनाओं से लोगों की जान को खतरा बनाने पर पुलिस ने एनएचएआई व पीडब्लूडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेलनगर में तैनात एसआई जयवीर सिंह ने एनएचएआई व पीडब्लूडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि नवनिर्मित राष्ट्रीय राज मार्ग एनएच 72 ए दिल्ली पॉंटा राष्ट्रीय राज मार्ग स ंचालित निर्मित कार्यदायी संस्था एनएचए आई व पीडब्लूडी के द्वारा यातायात को सुचारू संचालन हेतु साइन बोर्ड यातायात चिन्ह यातायात रिफलेक्टर चेतावनी संकेत की प्रयाप्त व्यवस्था व मार्ग को स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया जाना जिस कारण मार्ग पर किनारे पर गड्डे होने के कारण दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होना जिस कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु व घायल होने के कारण आमजन मानस में रोष व्याप्त होना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद हजारों रुपये की कटौती: आहूजा

संवाददाता

देहरादून। सौरभ आहूजा ने कहा कि त्योहारों के इस महत्वपूर्ण समय में नगर निगम द्वारा गैर-स्थायी पर्यावरण मित्रों के वेतन से 2,000 से 3,000 रुपये तक की कटौती किए जाने का मामला सामने आया है।

आज यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी युवा) के उत्तराखंड प्रदेश समन्वयक सौरभ आहूजा ने कहा कि एक ओर देश प्रदेश में दीपावली और अन्य त्योहारों को लेकर उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी ओर देहरादून शहर को स्वच्छ रखने वाले पर्यावरण मित्रों को अपने ही वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। त्योहारों के इस महत्वपूर्ण समय में नगर निगम द्वारा गैर-स्थायी पर्यावरण मित्रों के वेतन से 2,000 से 3,000 रुपये तक की कटौती किए जाने का मामला सामने आया है। आहूजा ने कहा कि नगर निगम में कार्यरत गैर-स्थायी पर्यावरण मित्रों को मात्र 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। ऐसे में उनके वेतन से 2,000 से 3,000 रुपये की कटौती करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। त्योहारों के समय जब हर परिवार कपड़े, मिठाइयां और जरूरी सामान खरीदने की उम्मीद करता है, तब इन कर्मचारियों के घरों में आर्थिक संकट खड़ा करना कहां का न्याय है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पर्यावरण मित्रों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। लेकिन हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। घोषणा के बाद अब मौजूदा वेतन में ही कटौती होना सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है। सौरभ आहूजा ने सवाल उठाया कि क्या सरकार की संवेदनाएं केवल मंचों, भाषणों और त्योहारों पर दिए जाने वाले बयानों तक ही सीमित हैं? क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि जिन पर्यावरण मित्रों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, उन्हीं कर्मचारियों के वेतन से त्योहारों के समय हजारों रुपये क्यों काटे जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा वाल्मीकि जयंती पर घोषित वेतन वृद्धि को शीघ्र लागू किया जाए। वेतन कटौती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सौरभ आहूजा ने कहा कि यह दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। एनसीपी युवा पर्यावरण मित्रों के सम्मान, अधिकार और आर्थिक न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। यदि नगर निगम प्रशासन ने शीघ्र इस मामले का समाधान नहीं किया, तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर शासन तक आवाज बुलंद करेगी।

23 साल पुराना जैनी प्रकरण फिर सुर्खियों में

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में पुराने मामलों के राजनीतिक पुनर्जीवन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग अब करीब 23 साल पुराने जैनी प्रकरण तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मामले का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सवाल उठाए। जवाब में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता डा. हरक सिंह रावत ने भट्ट पर पलटवार करते हुए उन्हें ही डीएनए जांच कराने की चुनौती दे दी। इस सियासी घमासान के बीच अब खुद को जैनी बताने वाली महिला का वीडियो सामने आया है। उसने नेताओं पर अपने नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने और अपने चरित्र पर लांछन लगाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह वर्ष 2003 की घटना का सच सबूतों के साथ सामने रखेगी।

जैनी प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति में अचानक आई तेजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि इस बार मामला केवल भाजपा और कांग्रेस के आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है। करीब ढाई दशक बाद खुद को इस प्रकरण का केंद्र बताने वाली महिला के सामने आने और खुलासे का दावा करने से राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने जैनी प्रकरण को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यह मामला कांग्रेस शासनकाल का है। उस समय जैनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चे के पिता की पहचान का तथ्य अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? भट्ट ने यह भी कहा कि उस समय जैनी ने तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम लिया था और इस प्रकरण से जुड़े तथ्यों को सामने आना चाहिए। भट्ट के इस बयान ने पुराने मामले को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया।

महेंद्र भट्ट के सवालों पर हरक सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैनी प्रकरण में उनकी डीएनए जांच हो चुकी है और जांच में वह निर्दोष साबित हुए हैं। जब जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो बार-बार उसी मामले को उछालने का औचित्य क्या है? हरक ने महेंद्र भट्ट पर पलटवार करते हुए उनके डीएनए परीक्षण की मांग तक कर डाली। इससे मामला और तूल पकड़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी भट्ट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरक सिंह रावत को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की सलाह दी। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चार नवंबर को सामने आए उस वीडियो से आया, जिसमें खुद को जैनी बताने वाली महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ने का ऐलान किया। महिला ने कहा कि नेताओं ने उसके नाम को राजनीतिक हथियार बना दिया है, जबकि इतने वर्षों में किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था।

उसने कहा कि वर्ष 2003 की घटना का सच वह खुद बताएगी और इसके लिए

◆हरक ने महेंद्र भट्ट को दी डीएनए जांच की चुनौती, अब सामने आई जैनी
◆भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोपों की सियासी जंग में पुराने मामले की एंट्री

उसके पास सबूत भी हैं। महिला ने एक दिन का समय मांगते हुए कहा कि वह प्रमाणों के साथ सामने आएगी। उसने यह भी कहा कि घटना के समय उसकी उम्र करीब 16-17 वर्ष थी और उसे डराया-धमकाया गया था। महिला ने डीएनए जांच कराने की बात भी कही है। हालांकि, उसके दावों, पहचान और बताए गए तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वह अपने दावे के समर्थन में कौन से दस्तावेज और प्रमाण सार्वजनिक करती है। वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया था, जब असम मूल की जैनी ने देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया और तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया। उस समय प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी।

मामले ने इतना राजनीतिक तूल पकड़ा कि 18 जून 2003 को विधानसभा में भी इसे लेकर हंगामा हुआ। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बाद में केंद्र सरकार की संस्तुति पर सीबीआई ने जांच शुरू की। जांच के दौरान कराए गए डीएनए परीक्षण में बच्चे का नमूना हरक सिंह रावत के डीएनए से मेल नहीं खाया। इसके बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिली। वर्ष 2016 में भी यह मामला फिर चर्चा में आया था। उस समय जैनी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए जाने की खबरें सामने आई थीं। इस तरह यह प्रकरण अलग-अलग राजनीतिक दौर में बार-बार सुर्खियों में लौटता रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक संदर्भ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस वीआईपी की भूमिका और जांच को लेकर सवाल उठा रही है। जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस शासनकाल के पुराने विवादों का उल्लेख कर पलटवार किया। इसी क्रम में जैनी प्रकरण फिर चर्चा में आया। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के विवादित मामलों पर भी जवाब देना चाहिए, जबकि कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। जैनी के वीडियो ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। हरक सिंह रावत जहां पहले की जांच का हवाला देकर खुद को निर्दोष बता रहे हैं, वहीं महेंद्र भट्ट के सवालों ने भाजपा-कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ा दिया है। अब खुद को जैनी बताने वाली महिला के दावों ने इस प्रकरण को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला जिन सबूतों के साथ सामने आने की बात कह रही है, उनमें ऐसा क्या है जो 23 साल पुराने घटनाक्रम पर नई रोशनी डाल सकता है? क्या उसके दावे पुराने मामले को नया कानूनी मोड़ देंगे या यह विवाद भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सिमटकर रह जाएगा?फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में जैनी प्रकरण फिर गर्म है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी से अधिक जरूरी है कि महिला के दावों को गंभीरता से सुना जाए, तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी व्यक्ति के बारे में फैसला आरोपों के बजाय प्रमाणों के आधार पर हो।

मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे एक जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।

दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार, दो बाइक बरामद

हमारे संवाददाता

देहरादून। वाहन चोरी मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनकी निशानदेही पर चोरी की दो बाइक बरामद हुई है। आरोपी नशे के आदी है जिन्होने नशापूर्ति के चलते इन वारदातों को अंजाम दिया था।



जानकारी के अनुसार बीती 2 नवम्बर को मोहम्मद खुर्रम पुत्र मेहरबान निवासी वन बिहार मेंहूवाला, पटेल नगर द्वारा अपने दुपहिया वाहन के चोरी होने के संबंध में कोतवाली पटेलनगर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी गयी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बीती रात एक सूचना के बाद महाराणा प्रताप पार्क में चैकिंग के दौरान घटना में शामिल 2 आरोपियों को घटना में चोरी किए गए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ मे उन्होने अपना नाम नासिर उर्फ माठू पुत्र बाबू अहमद निवासी आजाद कॉलोनी पटेल नगर व सादिक उर्फ सोनू पुत्र शहीद निवासी ग्राम माधोपुर थाना गंग नहर जनपद हरिद्वार बताया। पूछताछ में आरोपियो द्वारा बताया गया कि वह दोनों नशे के आदी हैं तथा अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके द्वारा उक्त वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर प्रेम नगर क्षेत्र से चोरी किया गया एक अन्य वाहन भी बरामद किया गया है।

कुम्भ मेला-2027: सीएम ने हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के मेला चिकित्सालय एवं भूपतवाला चिकित्सालय के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय परिसर से आगामी कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के मेला चिकित्सालय एवं भूपतवाला चिकित्सालय के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि उद्योग विकास परिषद के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे इन उपकरणों का उद्देश्य कुम्भ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुम्भ मेला-2027 में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि कुम्भ मेले के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के



विस्तार के साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। मेला चिकित्सालय एवं भूपतवाला चिकित्सालय के लिए उपलब्ध कराए जा रहे चिकित्सा उपकरण आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्राथमिक उपचार प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कृषि उद्योग विकास परिषद की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए कहा कि कुम्भ जैसे बड़े धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कुम्भ मेला-2027 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।